



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2011 (चैत्र 26, 1933)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16—APRIL 22, 2011 (CHAITRA 26, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

केनरा बैंक

बेंगलूर, दिनांक 17 फरवरी 2011

No. PWPM 9098 78 DK: केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5वाँ) की धारा 19 एवं धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, केनरा बैंक अधिकारियों का सेवा विनियम 1979 को आगे अशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम करता है :-

1. (1) इन विनियमों को केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 2010 कहा जाएगा ।
(2) संबंधित विनियमों में अन्यथा कहे गए संदर्भों को छोड़कर ये विनियम जून महीने के दूसरा दिन 2005 से लागू होंगे ।
2. केनरा बैंक अधिकारियों का सेवा विनियम 1979 के विनियम 3 में -
 - (i) उप खंड (g) हेतु निम्नलिखित उप खंड प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(g) "परिवार" का अर्थ अधिकारी का पति / की पत्नी (जो बैंक का कर्मचारी न हो) अविवाहित बच्चे (अश्रित सौतेले और कानूनन गोद लिए गए बच्चे समाहित) और अधिकारी पर पूर्णतया अश्रित, सामान्यतः उनके साथ रहनेवाले माता / पिता है ।
 - (ii) उप खंड (o) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(o) "पूर्णतया अश्रित बच्चे या माता-पिता" का मतलब है - बच्चे या माता-पिता जिनकी मासिक आय ₹2,550 से ज्यादा न हो ।

नोट

अगर माता या पिता की मासिक आय ₹2,550 से ज्यादा है या दोनों की कुल आय ₹2,550 से ज्यादा होने पर पूर्णतया अश्रित माता-पिता नहीं कहलायेंगे।

3. कथित विनियम के उप-विनियम(4) को निम्नलिखित उप-विनियम से प्रतिस्थापित किया

जाएगा।

'(4) 01 नवंबर 2002 को या उस तारीख से प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्धारित वेतन मान निम्नानुसार होगा:

(a) उच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतन मान VII ₹ 29340 - $\frac{680}{2}$ - 30700 - $\frac{900}{1}$ - 31600 - $\frac{1000}{1}$ - 32600

वेतन मान VI ₹ 26620 - $\frac{680}{4}$ - 29340

(b) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतन मान V ₹ 24140 - $\frac{620}{4}$ - 26620

वेतन मान IV ₹ 20480 - $\frac{560}{1}$ - 21040 - $\frac{620}{5}$ - 24140

(c) मध्य प्रबंधन श्रेणी

वेतन मान III ₹ 18240 - $\frac{560}{5}$ - 21040 - $\frac{620}{2}$ - 22280

वेतन मान II ₹ 13820 - $\frac{500}{1}$ - 14320 - $\frac{560}{10}$ - 19920

(d) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतन मान I ₹ 10000 - $\frac{470}{6}$ - 12820 - $\frac{500}{3}$ - 14320 - $\frac{560}{7}$ - 18240

नोट :-

यथा 31, अक्टूबर 2002 को लागू रहनेवाले वेतनमान के अनुसार प्रत्येक अधिकारी को इस उप विनियम यथा 01, नवंबर 2002 में निर्धारित किए जानेवाले वेतनमान में चरण दर चरण के आधार पर रखा जाएगा यानि तत्संबंधी वेतन मानों में तदुपरांत चरणों में प्रथम चरण के बाद और यथानुसार प्रथम वेतन वृद्धि वर्ष पर लागू होगा बशर्ते कि अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया हो।

(4A) उप विनियम (1),(2), और (3) में किसी उल्लेख का आशय यह नहीं है कि सभी श्रेणियों में अधिकारियों का सेवारत होना बैंक के लिए सदैव अपेक्षित हो।

4. कथित विनियमों में विनियम 5 का, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानि :

'5 वेतन वृद्धि (1) 01, नवंबर 2002 को और उस तारीख से विनियम 4 के उप विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार, मंजूर की जाएंगी :-

- a. विनियम 4 के उप-विनियम (4) में, उल्लिखित विनिर्दिष्ट वेतन वृद्धियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जाएंगी और वार्षिक आधार पर दी जाएंगी और जिस मास में ये देय होंगी उस मास के पहले दिन ही मंजूर की जाएगी।

- b. वेतन मान I और वेतन मान II के अधिकारी, अपने संबद्ध वेतन मानों में अधिकतम स्तर तक पहुँचने के, एक साल के बाद, सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्यक्षमता सीमा पार करने की शर्त पर निम्नलिखित (c) में किये गये उल्लेख के अनुसार, अगले उच्च वेतन मान में गत्यावरोध वेतन वृद्धि (यों) को सम्मिलित कर आगे वेतनवृद्धियों को मंजूर किया जाएगा ।
- c. उपर्युक्त खंड (b) में बताए गए अधिकारियों सहित, ऐसे सभी अधिकारी जो मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतन मान II और IV का अधिकतम सीमा तक पहुँचते हैं, जैसी भी स्थिति हो वेतन मान II या वेतन मान III के अंतिम चरण तक पहुँचने के बाद गत्यावरोध वेतनवृद्धि(यों) आहरित करेंगे, लेकिन वे वेतन मान II के अंतिम चरण में अधिकारियों के लिए ₹ 560/- के अधिकतम दो वैसे वेतनवृद्धि और वेतन मान III के अंतिम चरण में अधिकारियों के लिए ₹ 620/- के अधिकतम एक वैसी वेतनवृद्धि आहरित करेंगे ।

बशर्ते कि 01, नवंबर 1994 को या वेतनमान III में शामिल अधिकारी यानी वेतन मान III में भर्ती किए गए या पदोन्नत किए गए अधिकारी प्रथम गत्यावरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के तीन सालों के बाद दूसरी गत्यावरोध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे ।

बशर्ते कि पदोन्नति इनकार करनेवाले अधिकारी को ऐसी वेतन वृद्धि/याँ अगले वेतन मान / गत्यावरोध वेतन वृद्धि/याँ नहीं दिया जाएगा ।

नोट :

अगले उच्च वेतन मान में वैसी वेतन वृद्धियों की मंजूरी का मतलब पदोन्नति नहीं है । अधिकारी वैसी वेतन वृद्धियों को प्राप्त करने के बाद भी, अपने वेतन मान I या वेतन मान II जैसे भी स्थिति हो, अपने विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, कर्तव्य, दायित्व प्राप्त करते रहेंगे ।

- (2) पार्ट I सी.ए.ए.बी./ भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट और पार्ट II / भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणीकृत एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतन मान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूर की जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

- a. यदि कोई अधिकारी नियुक्ति तारीख से पहले अधिकारी के पद में भारतीय बैंकर्स संस्थान के पार्ट I या पार्ट II प्रमाणीकृत एसोसिएट परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तो, अतिरिक्त वेतन वृद्धि या वेतन वृद्धि नियुक्ति तारीख से प्रभावित होगी बशर्ते कि वह कथित परीक्षा की दोनों परीक्षाएं उत्तीर्ण करने हेतु, कोई भी वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं की हो या केवल एक वेतन वृद्धि प्राप्त की हो ।
- b. 01/11/1987 को या उस तारीख से, ऐसे अधिकारी जो वेतनमान में अधिकतम स्तर तक पहुँच चुके हैं या पदोन्नति के बिना आगे वेतन नहीं बढ़ता है तो, यदि सरकारी मार्गनिर्देश कोई हो तो, सी.ए.आई.आई.बी. परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि मंजूर करने के बदले व्यावसायिक अर्हता भत्ता निम्नानुसार मंजूर किया जा सकता है :-

सारणी

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. पार्ट I उत्तीर्ण किया है	i ₹ 100/- प्रति माह, एक साल बाद, जिसमें ₹75/- अधिवार्षिता लाभ में स्थान प्राप्त करेगा ।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों पार्ट उत्तीर्ण किया है	i ₹ 100/-प्रति माह, एक साल बाद, इसमें ₹75/- अधिवार्षिता लाभ में स्थान प्राप्त करेगा ।
	ii ₹ 250/- प्रति माह, दो साल बाद, इसमें ₹200/- अधिवार्षिता लाभ में स्थान प्राप्त करेगा ।

- c. 01/11/1994 को और उस तारीख से, अन्य मामले एक समान होते हुए, व्यावसायिक अर्हता भत्ता की प्रमात्रा निम्नानुसार संशोधित होगा :-

सारणी

जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी. पार्ट I उत्तीर्ण किया है	i ₹ 120/- प्रति माह, वेतन मान की शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद ।
जिन्होंने सी.ए.आई.आई.बी.के दोनों पार्ट उत्तीर्ण किया है	i ₹ 120/- प्रतिमाह , मान का शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद । ii ₹ 300/- प्रति माह, मान का शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद ।

बशर्ते कि अधिकारी जो विनियम 5(3) (ख) के मानदंड के अनुसार निश्चित वैयक्तिक भत्ता आहरित करने हेतु पात्र हैं, वे पार्ट I और पार्ट II के लिए क्रमशः वैसे निश्चित वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के एक साल / दो सालों के बाद, व्यावसायिक अर्हता भत्ता आहरित करेंगे ।

- d. 01/11/1999 को या उस तारीख से, अन्य मामले एक समान होते हुए, व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रमात्रा निम्न सारणी के अनुसार संशोधित रहेगा ।

सारणी

जिन्होंने जे.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण किया है	i ₹ 150/- प्रति माह, वेतन मान की शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद ।
जिन्होंने जे.आई.आई.बी. और सी.ए.आई.आई.बी. पार्ट I या सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों पार्ट उत्तीर्ण किया है	ii ₹ 150/- प्रतिमाह , मान का शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद । iii ₹ 360/- प्रति माह, मान का शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद ।

बशर्ते कि अधिकारी जो वेतन मान I और II में और जिन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्च वेतन मान में आगे वेतन वृद्धियाँ मंजूर की जाती हैं, उन्हें एक साल / दो सालों के बाद व्यावसायिक अर्हता वेतन, वैसे उच्च वेतन मानों में अधिकतम स्तर पहुँचने पर, आहरित करेंगे ।

- e. 01/11/2002 को या उस तारीख से, अन्य मामले एक समान होते हुए, व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रमात्रा निम्न सारणी के अनुसार संशोधित रहेगा ।

सारणी

जिन्होंने जे.आई.आई.बी. या सी.ए.आई.आई.बी. पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण किया है	₹ 300/- प्रति माह, वेतन मान की शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद ।
जिन्होंने जे.आई.आई.बी. और सी.ए.आई.आई.बी. पार्ट I या सी.ए.आई.आई.बी. के दोनों पार्ट उत्तीर्ण किया है	₹ 300/- प्रतिमाह , मान का शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद । ₹ 750/- प्रति माह, मान का शिखर पर पहुँचने के एक साल बाद ।

बशर्ते कि अधिकारी जो वेतन मान I और II में और जिन्हें उप-विनियम (1) (ख) के अनुसार अगले उच्च वेतन मान में आगे वेतन वृद्धियाँ मंजूर की जाती हैं, उन्हें एक साल / दो सालों के बाद व्यावसायिक अर्हता वेतन, वैसे उच्च वेतन मानों में अधिकतम स्तर पहुँचने पर, आहरित करेंगे।

नोट :

- i. व्यावसायिक अर्हता वेतन प्राप्त करनेवाले किसी अधिकारी की यदि पदोन्नति अगले उच्च वेतन मान में होती है तो, उस वेतन मान में उपलब्ध वेतन वृद्धियों के विस्तार तक जे.आई.आई.बी. / सी.ए.आई.आई.बी. उत्तीर्ण होने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धियाँ उपलब्ध हैं और यदि वेतन मान में कोई भी वेतन वृद्धियाँ नहीं हैं तो, वेतन वृद्धि(याँ) के बदले में व्यावसायिक अर्हता वेतन के लिए पात्र होंगे।
 - ii. 01/11/1994 को और से व्यावसायिक अर्हता वेतन, मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता और अधिवार्षिकता लाभ के लिए अर्ह होंगे।
 - iii. पदोन्नति इनकार करनेवाले अधिकारी उपर्युक्त के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन के लिए पात्र नहीं होंगे।
 - iv. यदि कोई अधिकारी वेतन मान के शिखर पर पहुँचने के बाद जे.आई.आई.बी. / सी.ए.आई.आई.बी. (एक या दोनों पार्ट) उत्तीर्ण होने पर, व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किश्त के लिए पात्र होगा और व्यावसायिक अर्हता वेतन की अनुवर्ती किश्तों का आधार व्यावसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किश्त की वितरण तारीख होगा।
 - v. 02 जून 2005 को यदि कोई अधिकारी खंड (iv) में उल्लिखित किसी एक अर्हता प्राप्त की हों और प्रस्तुत उपलब्धी के लिए कोई वेतन वृद्धि या व्यावसायिक अर्हता वेतन प्राप्त नहीं किया है तो 01 नवंबर 2002 से या ऐसी अर्हता प्राप्त करने की तारीख से, जो पहले है, व्यावसायिक अर्हता वेतन के लिए पात्र होगा।
- (3) (a) यथा 01 नवंबर 1993 को बैंक की स्थाई सेवा में रहनेवाले समस्त अधिकारी उनके वेतन मान में एक अग्रिम वेतन वृद्धि पाएंगे और यथा 01 नवंबर 1993 को परिवीक्षाधीन अधिकारी उनके स्थाईकरण के एक साल बाद एक अग्रिम वेतन वृद्धि पाएंगे।

नोट : अग्रिम वेतन वृद्धि के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

- (b) यथा 01 नवंबर 1993 को यदि वेतन मान के अधिकतम स्तर पर या गत्यावरोध वेतन वृद्धि(याँ) प्राप्त कर रहे अधिकारी, 01 नवंबर 1993 से निश्चित वैयक्तिक भत्ता आहरित करेगा जो अंत में आहरित वेतन वृद्धि और 01 नवंबर 1993 को देय मंहगाई भत्ता सहित, आवास किराया भत्ता जो विनियम 22 की शर्तों के अनुसार लागू होनेवाली दर पर हैं, की तत्समान राशि होगी जो निम्न सारणी के अनुसार और आगे संशोधित किए जाने तक विधिमान्य रहेगी।

सारणी

वेतन वृद्धि घटक	यथा 01/11/1993 को महंगाई भत्ता	बैंक का आवास उपलब्ध कराये जाने पर संदेय कुल भत्ता
(क) ₹	(ख) ₹	(ग) ₹
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) 01 नवंबर 1999 को और उस तारीख से, अन्य मामलों एक समान होते हुए निश्चित वैयक्तिक वेतन, आवास किराया भत्ता यदि हो तो, निम्न सारणी के अनुसार दिया जाएगा :-

सारणी

वेतन वृद्धि घटक	यथा 01/11/1997 को महंगाई भत्ता	बैंक का आवास उपलब्ध कराये जाने पर संदेय कुल भत्ता
(क) ₹	(ख) ₹	(ग) ₹
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.58	608

- (d) 01 नवंबर 2004 को और उस तारीख से, अन्य मामलों एक समान होते हुए निश्चित वैयक्तिक वेतन, आवास किराया भत्ता यदि हो तो, निम्न सारणी के अनुसार दिया जाएगा और शेष सेवा काल में स्थायी रहेगा:-

सारणी

वेतन वृद्धि घटक	यथा 01/11/1999 को महंगाई भत्ता	बैंक का आवास उपलब्ध कराये जाने पर संदेय कुल व्यक्तिगत वेतन
(क) ₹	(ख) ₹	(ग) ₹
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

नोट :

- i निश्चित वैयक्तिक भत्ता / निश्चित वैयक्तिक वेतन, खंड (b) और (c) में कालम (ग) के तहत सूचित अनुसार, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को प्रदेय है जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।
- ii आवास किराया भत्ते के लिए अर्ह अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता / निश्चित वैयक्तिक वेतन संबंधित अधिकारी कर्मचारियों द्वारा आहरित (क) + (ख) + आवास किराया भत्ता रहेगा, जब विनियम 4 के उप विनियमन (2) और (3) में निश्चित संबद्ध वेतन मान का अंतिम वेतन वृद्धि का अर्जन किया जाता है।
- iii 01 नवंबर 1999 को और उस तारीख से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी किए जाने के कारण उप-विनियम (2) के तहत स्पष्टीकरण (ग) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन को जारी करने की अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

बशर्ते कि, पूर्व प्रावधानों के कारण, व्यावसायिक अर्हता वेतन की किशत जहाँ एक साल के लिए टाली गई है और वह 01 नवंबर 1999 को या बाद में जारी हेतु अनुसूचित है, वह इस तारीख से जारी की जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन की दूसरा किशत, यदि हो तो, 01 नवंबर 2000 को जारी की जाएगी।
- iv निश्चित वैयक्तिक भत्ता / निश्चित वैयक्तिक वेतन का वेतन वृद्धि घटक, अधिवार्षिता लाभों के लिए स्थान पाएगा।
- v अधिकारी जो उपर्युक्त (क) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि उपार्जित की है, वे निश्चित वैयक्तिक भत्ता / निश्चित वैयक्तिक वेतन की प्रमात्रा उपर्युक्त (ख) या (ग) में किये गये उल्लेख के अनुसार वेतन मान में अधिकतम स्तर पहुँचने के एक साल बाद आहरित करेंगे।

5. कथित विनियम के विनियम 21 में, उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप विनियम जोड़ा जाएगा :

“(4) 01 नवंबर 2002 को या उस तारीख से महंगाई भत्ता निम्नलिखित प्रकार से होगा :

- a. अखिल भारतीय औसतन कामगार संवर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) बेस 1960=100, के तिमाही औसत में 2288 बिंदुओं पर प्रत्येक चार बिंदुओं के चढ़ाव या उतराव के लिए महंगाई भत्ता संदेय है।

- b. 01, नवंबर 2002 से 31, जनवरी 2005 तक निम्नलिखित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता संदेय है:-
- ₹ 9,650/- प्लस तक वेतन का 0.18%
 - ₹ 9,650/- से ' 15,350/- प्लस के ऊपर वेतन का 0.15%
 - ₹ 15,350/- से ' 16,350/- प्लस के ऊपर वेतन का 0.09%
 - ₹ 16,350/- के ऊपर वेतन का 0.04%
- c. 01 फरवरी 2005 को या उस तारीख से महंगाई भत्ता वेतन का 0.18% संदेय होगा :

नोट :-

(A) महंगाई भत्ते के उद्देश्य हेतु 'वेतन' का मतलब है गत्यावरोध वेतन वृद्धियाँ सहित मूल वेतन ।

(B). विनियम 5 का उप विनिय (2) का स्पष्टीकरण (ग) और (घ) में विनिर्दिष्टता के अनुसार व्यावसायिक अर्हता भत्ता / व्यावसायिक अर्हता वेतन महंगाई भत्ता के लिए स्थान पाएंगे ।

6. कथित विनियमों में विनियम 22 को, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानि

'22 आवास किराया भत्ता (1) (a) - 01 नवंबर 1994 को और से, जहाँ बैंक द्वारा अधिकारी

को आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, वहाँ अधिकारी जिसे जिस वेतन मान में रखा गया है, उसमें प्रथम चरण में मूल वेतन की 4% राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उसे उक्त अधिकारी से वसूल किया जाएगा ।

(b) जहाँ अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा नहीं दी गई है, 01/11/1992 से निम्नलिखित दरों पर आवास किराया भत्ते के लिए पात्र होगा :-

सारणी

कॉलम I	कॉलम II
जहाँ कार्य स्थान निम्न प्रांतों में हो	प्रदेय आ.कि.भत्ता निम्नानुसार रहेगा
i सरकार के मार्गनिर्देश और समूह 'ए' परियोजना क्षेत्र के केंद्रों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'ए' संवर्ग के नगर	प्रति माह वेतन का 09%
ii क्षेत्र I और समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र के केंद्रों में स्थान	प्रति माह वेतन का 08%
iii समूह 'बी' यानी उपर्युक्त (i) और (ii) में न जोड़ी हुई जगह	प्रति माह वेतन का 07%

बशर्ते यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो, उन्हें संदेय आवास किराया भत्ता, उस प्रकार होगा, यानि, अधिकारी को जिस वेतन मान में रखा गया है उसके प्रथम चरण में, वेतन का 4% से अधिक वास्तविक किराया जो उसने प्रदत्त किया है या, उपर्युक्त कॉलम II के अनुसार प्रदेय आवास किराया भत्ते का 15% जो भी कम है ।

(2) (a) 01 नवंबर 2002 को और उस तारीख से, जहाँ बैंक द्वारा अधिकारी को आवासीय सुविधा दी गई है, वहाँ अधिकारी को जिस वेतन मान में रखा गया है, उसके प्रथम चरण में मूल वेतन का 1.75% की राशि, या आवास के लिए मानक किराया जो भी कम है, उसे अधिकारी से वसूल किया जाएगा।

(b) जहाँ बैंक द्वारा अधिकारी को कोई भी आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहाँ वह 01 नवंबर 2002 को और उस तारीख से निम्नलिखित दरों पर आवास किराया भत्ता के लिए पात्र रहेगा।

सारणी

कॉलम I	कॉलम II
निम्न कार्यस्थान हो तो	संदेय आ.कि. भत्ता निम्नानुसार रहेगा
समूह 'ए' में परियोजना क्षेत्र के केन्द्र और 'ए' संवर्ग के नगर	प्रति माह वेतन का 8.5%
'ए' संवर्ग के अन्य शहर और समूह 'बी' में परियोजना क्षेत्र के केन्द्रों में स्थान	प्रति माह वेतन का 7.5%
अन्य स्थान	प्रति माह वेतन का 6.5%

परंतु, यदि कोई अधिकारी किराया रसीद प्रस्तुत करता है तो उन्हें संदेय आवास किराया भत्ता, इस प्रकार होगी यानी अधिकारी को जिस वेतन मान में रखा गया है उसके प्रथम स्टेज में, वेतन का 2.5% से अधिक वास्तविक किराया, जो उसने अदा किया है या उपर्युक्त कॉलम II के अनुसार संदेय आवास किराया भत्ता, जो भी कम हो।

(3) जहाँ अधिकारी अपने स्वामित्ववाले आवास में निवास करते हैं, वहाँ वह उप विनियम 1(ख) और 2(ख) के प्रावधानों के अनुसार ही आवास किराया भत्ता प्राप्त करेगा जैसे कि, वह निम्नलिखित 'क' या 'ख' में से उच्चतर 12वाँ भाग से समतुल्य राशि दे रहा हो।

(A)

निम्नों का कुल :-

- आवास के संबंध में संदेय नगर पालिका कर
- भूमी के भाव सहित आवास के मूल भाव का 12% और यदि आवास, भवन का एक एक भाग है तो, भवन भूमि को लगनेवाला मूल भाव में आवास को लगनेवाला आनुपातिक हिस्से का भाव होगा और इसमें विशेष फीचर्स जैसे वातानुकूल के भाव शामिल नहीं होगा, या

(B)

आवास के नगरपालिका द्वारा मूल्यांकन के लिए लिया गया वार्षिक किराया मूल्य

स्पष्टीकरण :-

(1) इस विनियम का उद्देश्य के लिए 'मानक किराया' का मतलब है :-

- (a) बैंक के स्वामित्ववाले आवास के मामले में, मानक किराया की गणना सरकार में वर्तमान में विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।
- (b) जहाँ आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया जाता है, बैंक द्वारा संदेय करारबद्ध किराया या उक्त प्रक्रिया (A) के अनुसार गणन किया गया किराया जो भी कम हो।

(2) मकान किराया भत्ते का उद्देश्य के लिए "वेतन" का मतलब है गत्यावरोध वेतन वृद्धियाँ सहित मूल वेतन।

(3) 01 नवंबर 1994 को या उस तारीख से व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन मकान किराया भत्ते के लिए स्थान पाएंगे।

(4) इन विनियम में, उप विनियम (1) के उद्देश्य के लिए क्षेत्र I, क्षेत्र II और क्षेत्र III का मतलब निम्नानुसार है :-

क्षेत्र - I - 12 लाखों से अधिक जनसंख्या वाले स्थान

क्षेत्र - II - ऐसे सभी स्थान जिन्हें क्षेत्र I में सम्मिलित नहीं किया है।

7. कथित विनियमों में विनियम 23 को, निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

'23 अन्य भत्ते

1. 01 नवंबर 2002 को और उस तारीख से निम्नलिखित सारणी के कॉलम I में उल्लिखित स्थान में यदि वह सेवारत है तो, उस स्थान के लिए संदेय और कॉलम II में उल्लिखित दर पर शहर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया जाएगा।

सारणी

स्थान (I)	दर (II)
(a) क्षेत्र I में और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन का 4% परंतु अधिकतम ' 540/- प्रति माह
(b) 5 लाखों और उससे अधिक के स्थान और राज्य के राजधानियाँ और चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर और उक्त (क) में जो सम्मिलित नहीं है।	मूल वेतन का 3% परंतु अधिकतम ' 375/- प्रति माह
(c) अन्य स्थान	शून्य

2. 01 नवंबर 2002 को या उस तारीख से विशेष क्षेत्र भत्ता, विनियमों के सूची में उल्लिखित दरों के अनुसार होगा।

3. 01 नवंबर 2002 को या उस तारीख से अधिकारी, समूह 'ए' या समूह 'बी' में उल्लिखित परियोजना क्षेत्र में कार्यरत है तो, प्रति माह ₹ 210 या ₹ 185 परियोजना क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता के लिए क्षेत्र वर्गीकरण के अनुसार पात्र होगा।
4. 01 नवंबर 2004 को या उस तारीख से अधिकारी किसी स्थान से अकादमिक वर्ष के बीच में स्थानांतरित किया गया है और उनके बच्चे ऊपर विद्यालय या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रति माह ₹ 500 के हिसाब से, पदभार ग्रहण तारीख से अकादमिक वर्ष अंत तक, प्रति बच्चा पात्र होगा।

बशर्ते कि यह भत्ता सभी बच्चों के पढ़ाई समाप्ति तक समाप्त होगा।

5. 01 नवंबर 2005 को और से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उससे जुड़े परिलब्धियाँ को प्राप्त कर सकता है या अपने वेतन के अलावा प्रतिनियुक्ति भत्ता जो जो वेतन का 7.75% होता है, परंतु प्रति माह अधिकतम ₹ 1500/- आहरित कर सकता है और ऐसे भत्ते यदि वह उस जगह पर बैंक की सेवा में तैनात किया जाता है तो आहरित कर सकता है।

परंतु अगर उसे उसकी प्रतिनियुक्ति से तुरंत पहले जहाँ उसको तैनात किया गया था उसी जगह से कोई संगठन को प्रतिनियुक्त किया जाता है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता अपनी वेतन की 4% के हिसाब से अधिकतम राशि ₹ 750/- के लिए पात्र होगा।

बशर्त कि अधिकारी जो बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है तो प्रतिनियुक्ति भत्ता अपनी वेतन की 4% के हिसाब से अधिकतम राशि ₹ 750 के लिए पात्र होगा।

6. अगर कोई अधिकारी अपने वेतन मान से भी उच्च वेतन मान में स्थानापन्न होकर एक बार सात दिनों से कम न होते हुए या कलेंडर महीने के दौरान कुल सात दिनों तक कार्य करना पड़ता है तो, वह अपने वेतन का 6% के समतुल्य, उसके स्थानापन्न अवधि के लिए प्रोराटा के आधार पर स्थानापन्न भत्ता के लिए पात्र होगा और स्थानापन्न भत्ता का उद्देश्य भविष्य निधि और पेंशन के लिए वेतन माना जाएगा।

बशर्ते विनियम 6 के तहत पदों का संवर्गीकरण के कारणों के परिणाम से यदि कोई अधिकारी उच्च वेतन मान में स्थानापन्न के लिए आता है तो संवर्गीकरण की समीक्षा प्रभारित होने की तारीख से एक साल तक स्थानापन्न भत्ता के लिए पात्र नहीं होगा।

7. यदि अधिकारी का स्थानांतरण ऐसी शाखा में होता है जहाँ लेखाबंदी 1 अप्रैल और 30 सितम्बर को होती है तो उसे प्रत्येक लेखाबंदी के लिए ₹ 250 दिया जाएगा।
8. 1 नवम्बर 2002 को और उस तारीख से यदि दिन के दौरान कार्यावधि न्यूनतम दो घंटों के अंतराल के लिए विभक्त है तो अधिकारी को ₹. 125 प्रति माह की दर पर विभक्त ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा।
9. यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के दिन तिजोरी या लॉकर के अभिरक्षक का कार्य करना पड़ता है तो वह अपनी पात्रता दर पर डीम भत्ते के लिए पात्र है।

10. 1 नवम्बर 2002 को और उस तारीख से निम्नलिखित सारणी के कॉलम 1 में उल्लिखित स्थान में याद अधिकारी सेवारत है तो, वह कॉलम 2 में उल्लिखित दर पर पहाड़ी और ईंधन भत्ता प्राप्त करेगा:

सारणी

	स्थान	दर
	(1)	(2)
(i)	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के स्थान	अधिकतम रू.1150 प्रति माह के अधीन वेतन का 5%
(ii)	1500 मीटर्स व उससे अधिक मगर 3000 मीटर्स से कम ऊंचाई के स्थान	अधिकतम रू.500 प्रति माह के अधीन वेतन 2 %
(iii)	1000 मीटर्स व उससे अधिक मगर 1500 मीटर्स से कम ऊंचाई के स्थान और मेरकरा टाऊन	अधिकतम रू. 400 प्रति माह के अधीन वेतन का 2%

नोट: (क) ऐसे अधिकारी जिन्हें 750 मीटरों से कम न होने वाली ऊंचाई पर तैनात किया गया है मगर वह स्थान ऐसे पहाड़ों से आवृत्त है और उस स्थान पर पहुँचने के लिए 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई को पार करनी पड़ेगी, ऐसे स्थानों पर तैनात अधिकारियों को प्रदेय दर पर ही पहाड़ी और ईंधन भत्ता दिया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं होनेवाले किसी केंद्र पर यदि पहाड़ी और ईंधन भत्ता वर्तमान में दिया जा रहा है तो वैसी सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।

परंतु अधिकारी जो ऐसे केंद्रों पर 1 मई 1989 से पहले तैनात किया गया है और उस तारीख के बाद भी वहीं तैनात रहता है तो 30 अप्रैल 1980 को उसके द्वारा आहरित भत्ते की प्रमत्ता की रक्षा की जाएगी और उसे प्रति माह तब तक दी जाएगी जब तक वह उसी वेतनमान में उसी केंद्र में तैनात रहेगा।"

8. कथित विनियमों में, विनियम 24 के लिए निम्नलिखित विनियम स्थानापन्न किया जाएगा:

24. चिकित्सा सहायता

(1) अपने और अपने परिवार के संदर्भ में किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अधिकारी निम्नलिखित आधार पर पात्र होगा:

(क) चिकित्सा व्यय: 1 फरवरी 2004 को और उस तारीख से अधिकारी को उसके परिवार को चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति, वैसे व्यय किए जाने के लिए स्वयं से व्यय किए जाने के प्रमाण पत्र साथ ही दावा की गई राशि के लिए खातों की विवरणी भी दी जाने पर निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट निश्चित सीमा राशि तक की जाएगी।

सारणी

श्रेणी	प्रतिपूर्ति सीमा
कनिष्ठ प्रबंधन और मध्य प्रबंधन श्रेणी	₹. 3750 या व्यय राशि, दोनों में जो भी कम हो।
वरिष्ठ प्रबंधन और उच्च कार्यपालक श्रेणी	₹. 5000 या व्यय राशि, दोनों में जो भी कम हो।

नोट: (i) अधिकारी उपयोग नहीं की गई चिकित्सा सहायता संचित कर सकता है, परंतु उसे उक्त उपलब्ध अधिकतम राशि का तीन गुना नहीं होना चाहिए।

(ii) वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुपातिकता से ग्यारह महीनों यानि फरवरी 2004 से दिसम्बर 2004 के लिए बढ़ायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: " इस विनियम के उद्देश्य के लिए अधिकारी के परिवार का मतलब विनियम 3 के खंड (g) में परिभाषित परिवार होगा।

(ख) (i) अस्पताल में भर्ती होने के सभी मामलों में अधिकारी के मामले में 100% और परिवार के सदस्यों के मामले में 75% अस्पताल भर्ती प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ii) 1 मई 2005 को और उस तारीख से इस विनियम के तहत अधिकारी को अस्पताल भर्ती व्ययों की प्रतिपूर्ति निम्न टेबल में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन दिनांक 2 जून 2005 के द्विपक्षीय समझौता के तहत अस्पताल भर्ती योजना की शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

सारणी

(क) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II व III	(i) शायिका प्रभार स्वयं - ₹ 600 प्रति दिन परिवार - ₹ 450 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार- कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल भर्ती योजना के तहत दी गई सीमा का 125%
(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान IV व V व उच्च कार्यपालक श्रेणी वेतनमान VI व VII	(i) शायिका प्रभार स्वयं-₹ 800 प्रति दिन परिवार-₹ 600 प्रति दिन (ii) अन्य प्रभार - कामगार कर्मचारियों के लिए लागू अस्पताल भर्ती योजना के तहत दी गई सीमा का 150%

(2) चिकित्सा हित (अस्पतालीकरण आदि समाहित) के उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट होने के बावजूद यदि बोर्ड बैंक में नियुक्ति की तारीख को चिकित्सा हितों (अस्पतालीकरण आदि समाहित) अपरिवर्तित रूप में बनाये रखना चाहते हैं तो सभी अधिकारी चिकित्सा हितों (अस्पतालीकरण आदि समाहित) के अनुमोदन के लिए बैंक में नियुक्ति की तारीख को बैंक द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पतालीकरण सुविधाएं निलंबित अधिकारियों के लिए भी अनुमेय हैं।

9. कथित विनियमों में, विनियम 25 को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

'25. निवासीय आवास: (1) कोई भी अधिकारी अधिकार के रूप में बैंक द्वारा निवासीय आवास उपलब्ध कराने हेतु हकदार नहीं होगा।

(2) फिर भी बैंक अपनी इच्छा से निवासीय आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए 1 नवम्बर 2002 को और उस तारीख से अधिकारी द्वारा अपने वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन का 1.75% से समान राशि या आवास के लिए मानक किराया जो भी कम है, दिया जाये।

बशर्ते कि जहाँ अधिकारी को वैसे निवास पर फर्नीचर उपलब्ध किया जाता है तो, अपने वेतनमान के प्रथम चरण में मूल वेतन का 0.4% से समान राशि बैंक द्वारा उससे वसूल किया जाएगा।

बशर्ते कि आगे जहाँ वैसे निवासी आवास बैंक द्वारा दिया गया है तो विद्युत, पानी, गैस और सफाई व्यवस्था के लिए प्रभार, अधिकारी द्वारा ही भरा जाएगा।

10. कथित विनियमों में, विनियम 41 में उप विनियम (1) को निम्नलिखित उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

(1) 2 जून 2005 को और उस तारीख से अधिकारी यात्रा के समय निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे:

(i) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2 टायर में रेल द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र है। तथापि, वह कारोबार अनिवार्यताओं या जन हित के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर हवाई जहाज (इकनोमी श्रेणी) में यात्रा कर सकता है।

(ii) मध्यम प्रबंधन श्रेणी का अधिकारी प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2 टायर में रेल द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र है या वह हवाई जहाज (इकनोमी श्रेणी) से यात्रा कर सकता है यदि दूरी 1000 कि मी से अधिक हो या छोटे मार्ग के लिए कारोबार अनिवार्यताओं या जन हित के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त हो।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में रेल द्वारा या हवाई जहाज (इकनोमी श्रेणी) द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र है।

(iv) जो स्थान हवाई मार्ग या रेल मार्ग द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं वहाँ वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक श्रेणी का अधिकारी कार द्वारा यात्रा कर सकता है परंतु दूरी 500 कि मी से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जब दो स्थानों के बीच का अधिकतम रास्ता हवाई या रेल मार्ग द्वारा पूरा हो सकता है तो सामान्यतः शेष दूरी कार द्वारा पूरा करना चाहिए।

(व) अन्य कोई भी अधिकारी कारोबार की अनिवार्यताओं के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर अपने वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा कर सकता है।

(ख) उप-विनियम (4) में खंड (क) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(क) विराम भत्ता - अधिकारी 1 जून 2005 को और उस तारीख से निम्नलिखित सारणी में बताए अनुसार विराम भत्ता 'पर डीम' पाने के लिए पात्र होगा।

सारणी

अधिकारियों श्रेणी /वेतनमान	प्रमुख 'क' वर्ग के शहर	क्षेत्र 1	अन्य स्थान
1	2		
वेतनमान IV व उससे ऊपर के अधिकारी	₹.600	₹.550	₹.500
वेतनमान I/II/III के अधिकारी	₹.550	₹.500	₹.400

वेतनमान IV व उच्च के अधिकारियों के मामले में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई, इन चारों महानगरों में बाहरी कार्य पर हो तो प्रति डीम देय विराम भत्ता रु 700 होगा।

आगे यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 4 घंटों से अधिक मगर आठ घंटों के अंदर ही होती है तो विराम भत्ता, उपर्युक्त दर में से आधा दर पर देय होगा।

स्पष्टीकरण:

विराम भत्ते की गणना के लिए 'पर डीम' का मतलब है प्रत्येक अवधि 24 घंटे या उसके बाद की अवधि, यदि वायुयान से यात्रा है तो रवाना होने हेतु रिपोर्टिंग समय तथा अन्यो के मामलों में रवाना होने के समय को, यात्रा का आरंभिक समय और पहुँचने का वास्तविक समय को, पहुँचने का समय माना जाएगा। जहाँ अनुपस्थिति की अवधि 24 घंटों से कम है, यहाँ 'पर डीम' का मतलब है, 8 घंटों से कम न रहनेवाली अवधि।

कथित विनियमों में विनियम 42 में, उप विनियमन (3) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी:-

'3) 01 अप्रैल 1997 को और से , स्थानांतरण के अधीन अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, माल के बीमा आदि के लिए निम्नलिखित सारणी के आधार पर राशि हेतु पात्र होंगे :-

सारणी

श्रेणी	राशि
उच्च कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी	₹ 5,000
मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन	₹ 4,000

बशर्त कि 01 मई 2005 को और उससे उप विनियमन के प्रावधान लागू होंगे और शब्द व अंक '₹ 5,000' और '₹ 4,000' को '₹ 8,750' और '₹ 7,000' अक्षर, शब्द व अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

12) कथित विनियमों में, विनियमन 44 का निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा, यानी:-

'44 छुट्टी यात्रा रियायत

1. अधिकारी चार साल के प्रत्येक खंड में, अपने जन्म स्थान या वैकल्पिक रूप से एक खंड में जन्म स्थान और दूसरे खंड में भारत में कहीं भी छोटे रास्ते से जा सकता है।
2. एक अधिकारी जो जैसी भी स्थिति हो दो साल या चार साल में विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, वह छुट्टी यात्रा रियायत का नकदीकरण (जन्म स्थान विकल्प छोड़कर) भी कर सकता है, जिसके आधार पर, वेतन मान I के अधिकारी अधिकतम 4500 कि.मी. और वेतन मान II और III के अधिकारी अधिकतम 5500 कि.मी. (इकतरफा) के लिए योग्य रेल श्रेणी में योग्य राशि का 75% के लिए पात्र होंगे। वेतन मान IV और उच्चस्तर के अधिकारी अपने लिए और परिवार के सदस्यों को एक खंड में एक ही बार नकदीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। विशेष अधिकार छुट्टी का नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत नकदीकरण के साथ भी प्राप्त कर सकते हैं।
3. छुट्टी यात्रा रियायत के लिए यात्रा का प्रकार और श्रेणी और अन्य शर्तें वही होगा जो, अधिकारी साधारणतया स्थानांतरण के समय यात्रा के लिए योग्य होगा जो बोर्ड द्वारा समय - समय पर निर्धारित आधार पर होगा।
4. चार साल की अवधि में जब अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करता है, एक समय में अधिकतम 30 दिन विशेष अधिकार छुट्टी का नकदीकरण भी कर सकता है, या वह एक खंड में अपना जन्म स्थान और दूसरे खंड में भारत में कहीं भी जा सकता है और प्रत्येक खंड में अधिकतम 15 दिन का या एक खंड में अधिकतम 30 दिन का नकदीकरण कर सकता है और छुट्टी नकदीकरण के उद्देश्य के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करनेवाले माह में देय परिलब्धियाँ अनुमेय होगा।

अधिकारी, प्रधान मंत्री राहत निधि में विप्रेषण के लिए बैंक को प्राधिकृत करके एक पत्र देने से, प्रधान मंत्री राहत निधि में दान के लिए एक दिन का अतिरिक्त विशेष अधिकार छुट्टी का नकदीकरण कर सकता है।

ए के नाहर

महा प्रबंधक

नोट : मूल विनियमों को आधिकारिक राजपत्र सं. 15 दिनांक 14.04.1990 में प्रकाशित किया गया। निम्न अधिसूचनाओं के द्वारा औपरांतिक संशोधनों को अधिसूचित किया गया।

क्रमांक	राजपत्र अधिसूचना संख्या	दिनांक
1	42	19.10.1996
2	49	07.12.2002

केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 की अनुसूची
(विनियम 23 का उप-विनियम (2) देखें)

01 नवंबर 2002 को या से एक अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ता के लिए निम्नलिखित सारणी के आधार पर पात्र होंगे, यानि :-

सारणी

क्रमांक	वे स्थान जहाँ भत्ते संदेय हैं	देय भत्ते के दर	
		वेतन ₹10,000 से ₹14,000 तक	वेतन ₹14,001 से ऊपर
1	मिजोरम	₹	₹
	क) मिजोरम के चिम्तुईपुई जिला और लुंगले जिला के लुंगले शहर से 25 कि.मी. से दूरीवाले स्थान	1,000	1,300
	ख) मिजोरम के समस्त लुंगले जिले के लुंगले शहर से 25 कि.मी. से दूरीवाले स्थानों को छोड़कर अन्य स्थान	800	1,050
	ग) समस्त ऐज्वाल जिला	600	750
2	नागालैंड	800	1,050
3	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		
	क) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	800	1,050
	ख) उत्तर व मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, निकोबार और नार्कोडम द्वीप समूह	1,000	1,300
4	सिक्किम	1,000	1,300
5	लक्षद्वीप द्वीप समूह	1,000	1,300
6	असम	160	200
7	मेघालय	160	200
8	त्रिपुरा	800	1,050
	क) त्रिपुरा के दुर्गम इलाके		
	ख) दुर्गम इलाकों को छोड़कर अन्य इलाके	600	750
9	मणिपुर	600	750
10	अरुणाचल प्रदेश	1,000	1,300
	क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाके		
	दुर्गम इलाकों को छोड़कर अन्य इलाके	800	1,050

क्रमांक	वे स्थान जहाँ भत्ते संदेय हैं	देय भत्ते के दर	
		वेतन ₹10,000 से ₹14,000 तक	वेतन ₹14,001 से ऊपर
11	जम्मू कश्मीर क) कठुआ जिला 1) नियाबत बनी 2) लोही 3) मल्हर 4) मछोडी	1,000	1,300
	ख) 1) उधमपूर जिला 1) डुडु बसंतगढ 2) लैंडर भमाग इलाका 3) ठकरा कोठे 4) नागोटे	1,000	1,300
	2) 2 (ग) में सम्मिलित स्थानों को छोड़कर मोहरी तहसील के अन्य स्थान	1,000	1,300
	ग) कम्बन की तरफ से गोयल तक और केईसी की तरफ से अरनाम तक	800	1,050
	3) डोडा जिला किश्तवार तहसील के पादेर और नाईबाट नौगाँव के इलाके	1,000	1,300
	4) लेह जिला जिला के समस्त स्थान	1,000	1,300
	5) बारामुल्ला जिला क) पूरी गुरेज-नीराबात, टाँगदार उप-डिविशन और कीरान इलाका	1,000	1,300
	ख) मटचिल	800	1,050
	6) पूँज और राजौरी जिले पूँज और राजौरी शहरों तथा सुन्दरबानी शहर तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी इलाके छोड़कर पूँज और राजौरी जिले के शेष स्थान	600	750
	7) (1) से (6) तक न सम्मिलित जगहें जो नियंत्रण रेखा के 8 कि.मी. की दूरी के अंदर हैं या राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर अपने कर्मचारियों के लिए, भत्ते हेतु घोषित जगह	600	750

क्रमांक	वे स्थान जहाँ भत्ते संदेय हैं	देय भत्ते के दर	
		वेतन ₹10,000 से ₹14,000 तक	वेतन ₹14,001 से ऊपर
12	हिमाचल प्रदेश		
	1) चम्बा जिला		
	1) क) पानगी तहसील		
	1) ख) हारमर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें बागदौन, बाजोल, देव्ल कुग्ती, नयागँव और टुंडा		
	ग्राम : जगत ग्राम पंचायत का घाटु और चौहाटा ग्राम पंचायत का कानासी	600	750
	पार्ट 1 ख में शामिल पंचायतें व ग्रामों को छोड़कर भारमर तहसील		
	किन्नौर जिला	1,000	1,300
	क) निम्नलिखित पंचायत इलाकों को छोड़कर शेष इलाके असरांग, चिटकुल और हानगो कुनो / चरांग पंचायतें, ग्राम पंचायत छोटा खंभा, नाथपा और रूपी के 15/20 क्षेत्र और पूह सब-डिविशन		
	(क) में सम्मिलित इलाके छोड़कर पूरी जिला	600	750
	3) कुलु जिला	1,000	1,300
	3 क) निर्मद तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खारगा, कुम्हार और सरगा पंचायत है ।		
	3 ख) बाहरी सेरज (निर्मद तहसील के जकत-खाना और बुरोव छोड़कर) और पूरी जिला (बाहरी सेरज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगणा को छोड़कर लेकिन निर्मद तहसील के जकत खाना और बुरोव ग्राम सहित)	600	750
	4) लाहौल और स्पिति जिले	1,000	1,300
	दोनों जिलों के सारे इलाके		
	5) शिमला जिला	1,000	1,300
	क) रामपूर तहसील के 15/20 क्षेत्र यानी कि कूट, लबना-सदना, सरपारा और चाडी-ब्रंदा पंचायतें		
	ख) दोद्रा-कवार तहसील, रामपूर के डरकाली ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और परगणा शरहन के मुनिश, घोरी चैबिस	800	1,050
	ग) चोपल तहसील और परगणा शरहन के घोरिस, पंच गाँव, पतस नाँव, नौबीस और शरहान, तकलेश क्षेत्र के देवती ग्राम पंचायत, रामपूर तहसील के परगणा बराबीस, कसबा रामपूर और परगणा रामपूर के घोरी नोग, शिमला शहर और इसके उप नगर (धल्ली, जतोग, कसुमपति, मशोब्रा, तारादेवी और टुटु)	600	750

क्रमांक	वे स्थान जहाँ भत्ते संदेय हैं	देय भत्ते के दर	
		वेतन ₹10,000 से ₹14,000 तक	वेतन ₹14,001 से ऊपर
	6) कांग्रा जिला बारा भंगाल और छोटा भंगाल के इलाके	800	1,050
	ख) कांग्रा जिला का धर्मशाला शहर और निम्नलिखित कार्यालय जो नगर सीमा के बाहर हैं, लेकिन धर्मशाला नगर में शामिल हैं - दारी के महिला आई.टी.आई., रामनगर के यांत्रिक कार्यशाला, सकोह के बाल कल्याण और नगर आयोजना कार्यालय, लोवर सकोह के सी.आर.एस.एफ. कार्यालय, दुगियार के कांग्रा दूध आपूर्ति योजना, साधेर के एच.आर.टी.सी. कार्यशाला, दारी के क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, शामनगर के वन निगम कार्यालय, दारी चाय फाक्टरी, डान आई.पी.एच. सब-डिविशन, शामनगर निपटान कार्यालय, शामनगर बिनवा परियोजना, बनूरी कार्यालय / जर्सी फैर्म, बंडला सेरीकल्चर कार्यालय इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला / एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. डिविशन, लोहना बिजली सब-डिविशन, बंडला डी.पी.ओ. निगम, घुग्गार बिजली एच.पी.एस.ई.ई. डिविशन।	600	750
	7) मांडि जिला जोगीन्द्र नगर के छुहार घाटी, बाग्रा तुनास तहसील के पंचायतें, धरमपुर ब्लॉक के छात्री, छोटधार, गरागुशैन, गाटू, गयस, जंझेली, जयार, जोहार, कलहानी, कलवान, खोलानल, लोथ, सिलिबागी, सोमाचन, तचहधार, ताची, थाना पंचायतें, करसोग तहसील के -बिंगा, कमलाह, सकलाना, तन्यार और ताराखोला पंचायतें, सुन्दर नगर तहसील के बालिधर, बाग्रा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुधी, मंज, पेखी, साइंज, सराहन और तेबान पंचायतें, बोही, बटवारा, धन्यारा, पौरा-कोथी, सेरी और षोजा	600	750
	8) शिरमाउर जिला बानी, बखाली पंचायतें (पछाड तहसील), भरोग भेनेरी (पाओंता तहसील), बिरला (नहान तहसील), डिब्बेर (पछाड तहसील), और थाना कसोगा (नहान तहसील)	600	750
	ख) तांसगिरि जिला	600	750
	9) सोलान जिला मंगल पंचायत	600	750
	10) हिमाचल प्रदेश के वे स्थान जो (1) से (9) तक शामिल नहीं हैं।	160	200
13	उत्तर प्रदेश - चमेली, पितौरागढ़ और उत्तर काशी जिले के अधीन इलाके क) पितौरागढ़ जिला के अन्य इलाके तथा उत्तर काशी (उत्तर काशी के जिला मुख्यालय सहित) ख) चंपावत जिला (लोहाशाति उलाका सहित)	1,000	1,300
14	उत्तरांचल रुद्राप्रवाग और चंपावत जिले के अधीन इलाके	800	1,050

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च 2010

सं. एन-15/14/3/2010-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 01 फरवरी 2011 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा असम कर्मचारी राज्य बीमा नियम -1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ असम राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात् :--

“जोरहाट शहर के विस्तारित क्षेत्रों के अंतर्गत राजस्व वाले गांव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र-शोनारी गांव, हजारी गांव, बारमेटा चापोरी, पोकीमुरी हबी गांव चराऊबाही मौजा के भकत चेउनी गांव, गांव-बहाती गांव, भाती मोरा गांव, सरबाई बंधा गांव, सरूसराइ मौजा में बहातिया गांव, गांव पबतीया और खंडीया मौजा में चरंगिया गांव, कातोनी मौजा में काठकोतिया गांव और काटोनी गांव, गांव-गारामुर मौजा में दुलिया गांव, जोरहाट टाउन मौजा में लीचूबारी और जेल रोड और जोरहाट जिले में होलनगपार मौजा में चेनीजान गांव।

आर. सी. शर्मा
निदेशक (यो. एवं वि.)

CANARA BANK

Bangalore, the 17th February 2011

No. PWPM 9098 78 DK : In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Canara Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Canara Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.
2. In the Canara Bank (Officers') Service Regulation, 1979 (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3, -
 - (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely, -
'(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer';
 - (ii) for clause (o), the following clause shall be substituted, namely:-
'(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs.2,550 per month'

Note: If the income of one of the parents exceeds Rs.2,550 per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.2,550 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employees

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

'(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under: -

(a) Top Executive Grade:

$$\text{Scale VII} = \text{Rs.} 29340 - \frac{680}{2} - 30700 - \frac{900}{1} - 31600 - \frac{1000}{1} - 32600$$

$$\text{Scale VI} = \text{Rs.} 26620 - \frac{680}{4} - 29340$$

(b) Senior Management Grade:

$$\text{Scale V} = \text{Rs.} 24140 - \frac{620}{4} - 26620$$

$$\text{Scale IV} = \text{Rs.} 20480 - \frac{560}{1} - 21040 - \frac{620}{5} - 24140$$

(c) Middle Management Grade:

$$\text{Scale III} = \text{Rs.} 18240 - \frac{560}{5} - 21040 - \frac{620}{2} - 22280$$

$$\text{Scale II} = \text{Rs.} 13820 - \frac{500}{1} - 14320 - \frac{560}{10} - 19920$$

(d) Junior Management Grade:

$$\text{Scale I} = \text{Rs.} 10000 - \frac{470}{6} - 12820 - \frac{500}{3} - 14320 - \frac{560}{7} - 18240$$

Note: Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise;

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the bank to have at all times, officers serving in all these grades."

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely: -

'5. Increments - (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely: -

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) Officers in Scale I and Scale II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government;
- (c) Officers including those referred to in clause (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III, as the case may be, subject to a maximum of two such increments of Rs.560 each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620 for officers in the last stage of Scale III;

Provided that on and from the 1st day of November, 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment:

Provided further that such increment/s in the next higher scale/stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note: Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale-II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers/Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation: (a) in the case of an officer who has passed Part I or Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

(b) on and from the 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below:

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year of which Rs.75/- shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
	(ii) Rs.250 per month after two years, of which Rs.200 shall rank for superannuation benefits.

(c) on and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed: only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
Those who have passed: both Parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale.
	(ii) Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale.

Provided that officers who are eligible to draw Fixed Personal allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year/two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

(d) on and from the 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers ;	(i) Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
	(ii) Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

(e) on and from the 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below: -

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers:	(i) Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the scale; (ii) Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note : (i) if an officer who is in receipt of Professional Qualification Pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers/Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).

(ii) on and from 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and superannuation benefits.

(iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.

(iv) if an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.

(v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.

- (3)(a) all officers who are in the bank's permanent service as on the 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on the 1st day of November 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note: There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) an officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from the 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus House Rent Allowance, at such rates as applicable in terms of regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) on and from the 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below: -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1. 11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) on and from the 1st day of November, 2004 other things being equal, the Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service : -

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 1.11.2002 on the increment component	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note : (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under Column (C) of the tables in the clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.

(ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A)+(B)+House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation 5 drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of regulation 4 is earned.

(iii) on and from the 1st day of November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

(iv) the increment component of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.

(e) an officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.'

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

'(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under:

(a) dearness allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 = 100.

(b) during the period from the 1st day of November, 2002 to 31st day of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :-

(i) 0.18% of 'pay' upto Rs.9,650 plus

(ii) 0.15% of 'pay' above Rs.9,650 and upto Rs. 15,350 plus

(iii) 0.09% of 'pay' above 15,350 and upto Rs. 16,350 plus

(iv) 0.04% of 'pay' above Rs. 16,350

- (c) on and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note: (A) "Pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance.'

6. In the said regulation, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely:-

'22. House Rent Allowance - (1) (a) on and from the 1st day of November, 1999 where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 1999 the House Rent Allowance as specified in the Table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in (1)	HRA payable shall be (2)
(i) Major 'A' class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government and Project 'Area Centres in Group 'A'.	9% of the pay per month.
(ii) Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	8% of the pay per month.
(iii) Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above	7% of the pay per month.

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of

pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above table, whichever is lower.

(2)(a) On and from the 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(b) where an officer is not provided any residential accommodation by the bank, he shall be eligible on and from the 1st day of November, 2002 the House Rent Allowance as specified in the table below, namely: -

TABLE

Where the place of work is in	House Rent Allowance payable shall be
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	8.5% o of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B	7.5% of Pay
(iii) Other places	6.5% of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him/her shall be the actual rent paid by him/her for the residential accommodation in excess over 1.75% of Pay in the first stage of the scale of pay in which he/she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per column (2) of the above Table.

(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below:-

(A)

The aggregate of :-

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation; and
- (ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :

- (1) For the purpose of this regulation “standard rent” means :-
 - (a) in the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government.
 - (b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure specified in (A) above, whichever is lower.
- (2) “Pay” for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulations (1) and (2) of this regulation and regulation 23, Area I and Area II shall mean as under :-
 - Area – I - Places with a population of more than 12 lakhs
 - Area – II - All places not included in Area – I.’

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely: -

23. Other Allowances:

- (1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely,

TABLE

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c) Other places	Nil

- (2) On and from the 1st day of November, 2002 the rates of special area allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210 per month or Rs.185 per month according to the classification of area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance at the rate of Rs.500 per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children studying:

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1500 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4% of his pay subject to a maximum Rs.750 per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than seven days at a time or an aggregate of seven days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for the purposes of Provident Fund and Pension only:

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorization of posts under regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorization takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250 for each of the two closings.

- (8) On and from the 1st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125 per month.
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.
- (10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Place	Rate
(1)	(2)
(i) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1150 per month
(ii) Place with an altitude of 1 500 metres and above but less than 3000 metres	2½% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month

Note : (a) officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more, shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centers with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn:

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989 and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay.'

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely:-

24. Medical Aid:-

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:-

- (a) Medical Expenses:- On and from the 1st day of February, 2004 an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.

(ii) for the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months, i.e. from February 2004 to December 2004.

Explanation: - "Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

- (b)(i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalization.

- (ii) on and from the 1st day of May, 2005, reimbursement of hospitalisation expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with the terms and conditions of Hospitalisation Scheme laid down under the Bipartite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely:-

TABLE

(a) Junior Management Grade Scale I and Middle Management Grade Scales II and III.	<p>(i) Bed Charges Self - Rs.600 per day. Family - Rs.450 per day.</p> <p>(ii) Other charges - At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees</p>
(b) Senior Management Grade Scales IV and V and Top Executive Grade Scales VI and VII.	<p>(i) Bed Charges Self - Rs.800 per day. Family - Rs.600 per day.</p> <p>(ii) Other charges - At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.</p>

- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above, and in complete substitution of the same, the Board may decide to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization, etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms and conditions obtaining in the bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

(3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.'

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely:-

'25. Residential Accommodation.- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.

(2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.'

10. In the said regulations, in regulation 41, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

(1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-

- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.

- (ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms, or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
- (iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).
- (iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km, and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.
- (v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.
- (b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
- (a) Halting Allowance- On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to 'per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades/Scales of officers	Major 'A' Class cities	Area 1	Other Places
1	2		
Officers in Scale IV and above	Rs. 600	Rs. 550	Rs. 500
Officers in Scale I/II/III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale IV and above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation: For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

- '(3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely,

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive and Senior Management	Rs.5,000
Middle Manaaement and Junior Management	Rs.4.000

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.'

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely:-

'44 Leave Travel Concession:

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or; alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms (one way) for officers in JMG Scale I and MMG Scale II and III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time, or he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege ~~Leave~~ with a

maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible, :

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.'

A K NAHAR
GENERAL MANAGER

Foot Note : The principal regulations were published in the official Gazette No.15 dated 14.04.1990. The subsequent amendments were notified vide the following notifications:

Sr.No.	Gazette Notification No.	Date
1	42	19.10.1996
2	49	07.12.2002

Schedule to Canara Bank (Officers') Service Regulations, 1979
(See, sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:-

TABLE

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
1.	Mizoram	(Rs.)	(Rs.)
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. From Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1,050
	c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750
9.	Manipur	600	750
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District (a) Niabat Bani (b) Lohi (c) Malhar (d) Macchodi	1,000	1,300
	(2) (a) Udhampur District i. Dudu Basantgarh ii. Lander Bhamag Illaqa iii. Thakrakote iv. Nagote	1,000	1,300
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800	1,050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
	(3) Doda District Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil	1,000	1,300
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa b) Matchill	1,000 800	1,300 1050
	(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
	Himachal Pradesh (1) Chamba District 1(a) Pangi Tehsil	1000	1300
	1 (b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil (i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah	800	1050

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part 1 .b above.		
	3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	600	750
	(2) Kinnaur District: (a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Khamba, Nathpa and Rupi, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,000	1,300
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
	(3) Kullu District: 3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga. Kushwar and Sarga	1,000	1,300

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District: (a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana. Sarpara and Chadi-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan.	800	1,050
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghor Nog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
	(6) Kangra District: (a) Areas of Bara Bhangal and Chhota Bhangal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices. Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division. Dan, Settlement Office. Shamnagar, Binwa Project, Shamnagar, Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD) Division. Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750
	(7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag	600	750

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and above
	Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gato, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Sômachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil - Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil - Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.		
	(8) Sirmaur District: (a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil).	600	750
	(b) Thansgiri Tract		
	(9) Solan District : Mangal Panchayat.	600	750
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	160	200

Serial number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs. 10,000 to Rs. 14,000	Pay from Rs. 14,001 and Above
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts: 2(a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi). 2(b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300
14.	Uttaranchal: Areas under Rudraprayag and Champawat Districts.	800	1,050

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 17th March 2011

No. **N-15/14/3/2010-P&D** : In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the **1st February, 2011** as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the **Assam** Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, **1955** shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of **Assam** namely:-

"Areas under extended areas of Jorhat town falling under the Revenue Villages-Sonari Gaon, Hazari Gaon, Barbheta Chapori, Pokimuri Habi Gaon, Bhakat Cheuni Gaon in Charaibahi Mouza, Villages – Bahati Gaon, Bhati Mora Gaon, Sarbai-Bandha Gaon, Bahatia Gaon in Sarusarai Mouza, Villages – Charingia Gaon in Parbatia and Khandia Mouzas, Villages – Kathkotia Gaon and Katoni Gaon in Katoni Mouza, Villages – Dulia Gaon in Garamur Mouza, Lichubari & Jail Road in Jorhat Town Mouza and Chenijan Gaon in Hallungpar Mouza in the district of Jorhat."

R. C. SHARMA
Director (P & D)